विचार बिन्दु

नारी की उन्नति पर ही राष्ट्र की उन्नति या अवनति निर्धारित है। - अरस्तु

मुख्य सचिव की अधिकारियों को सही सलाह

राजस्थान के नए मुख्य सचिव सुधांश पंत ने वरिष्ठ अधिकारियों की पहली बैठक में यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी प्राथमिकता एवं अधिकारियों से अपेक्षा, आने वाले समय में क्या होगी?

वास्तव में ,यदि राज्य के सभी वरिष्ठ अधिकारी- विशेष कर भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा एवं अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं के अधिकारी इन्हें हृदयगत करते हुए उनके अनुसार काम करना प्रारंभ कर दें , तो राज्य की तस्वीर ही बदल सकती है। मुख्य सचिव ने यह तो नहीं कहा कि जो इस अपेक्षा के अनुसार काम नहीं करेंगे,उनके विरुद्ध किस प्रकार की कड़ी कार्यवाही की जाएगी, किंतु यह माना जा सकता है कि राज्य में प्रशासनिक तंत्र के मुखिया के रूप में उनकी सलाह को आदेश के रूप में लिया जाना ही अधिकारियों के लिए उपयुक्त होगा यह सलाह, इस परिप्रेक्ष्य में और भी अधिक आवश्यक है कि सामान्यतया अधिकारी गण विशेष कर उच्च सेवाओं के अधिकारी गण, जनता से इस प्रकार की दूरी बनाकर रखते हैं एवं इस प्रकार का व्यवहार करते हैं कि कई बार तो लोग यहां तक पूछते हैं कि क्या इन अधिकारियों को अहंकारी होने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है ? अंठोजों के जमाने में तो शायद इस प्रकार का प्रशिक्षण भी दिया जाता हो क्योंकि अधिकारियों से अपेक्षा की जाती थी कि वह अंठोज शासको की इच्छा पूर्ति के माध्यम बनें। अब, जबकि स्वतंत्र देश का शासन चुने हुए जनप्रतिनिधियों के हाथों में है, अधिकारियों द्वारा जनता से दूरी बनाए रखना उनके स्वयं के हित के विरुद्ध है। मुख्य सचिव की यह सलाह कितनी अच्छी है कि ''सही काम करने से न डरें और गलत काम करने से बचें''। सामान्यतया देखा गया है कि गलत से गलत काम भी यदि राजनीतिक आकाओं और उच्च अधिकारियों द्वारा करने हेतु कहा जाता है ,तो अधिकारीगण पूरे समर्पण भाव से उसको करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। दूसरी ओर सामान्य जन के बहुत उचित एवं उपयुक्त कार्य भी नहीं किये जाते हैं एवं उसके लिए उन्हें कई बार सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। यही वह बात है जिससे सरकार की छवि जन विरोधी बनती है। यदि इस प्रकार की कार्य पद्धित में बदलाव लाया जाए एवं मुख्य सचिव की भावना के अनुसार अधिकारीगण कार्य करना प्रारंभ कर दें तो कोई कारण नहीं कि वे जनता का विश्वास नहीं जीत पाएँ। तब, विभिन्न सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन भी अधिक प्रभावी रूप से कर पाएँगे। सरकार चाहे कितनी भी अच्छी योजनाएं क्यों न बना ले, उनका लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुचना तो इस पर निर्भर है कि राज्य की नौकरशाही, किस प्रकार से संवेदनशील होते हुए कार्य करती है। जब सरकार की योजनाओं पर धन तो व्यय होता ही है , फिर उसका लाभ सही व्यक्तियों तक न पहुंचना किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इसका प्रमुख कारण यह है कि अधिकारी केवल आंकड़ों में उलझ कर रह जाते हैं और यही अपेक्षा अपने अधीनस्थ अधिकारियों से भी करते हैं । अधिकारियों को चाहिए कि वह वस्तु स्थिति का पता करने के लिए एक साधारण नागरिक की तरह अपनी पहचान को बताए बिना साधारण जनता के साथ मिलते-जुलते रहें। वे यह देखें कि उनके विभागों का कार्य किस प्रकार से वंचित वर्ग के लोगों तक बिना किसी बाधा के पहुंच रहा है अथवा नहीं? यह देखा गया है कि सामान्यतया, सरकारी बैठकों में अधीनस्थ अधिकारी गण प्रत्येक योजना की अच्छी क्रियान्विति की सुंदर तस्वीर कलेक्टर, सचिव अथवा अन्य उच्च अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं और उसी को सही मानते हुए वे संतुष्ट हो जाते हैं जबकि वास्तविकता कई बार इसके ठीक विपरीत होती है ।जिन अधिकारियों ने आकस्मिक रूप से जनता के बीच जा कर, उन्हें विश्वास में ले कर उनकी कठिनाइयों और समस्याओं को जानने का प्रयास किया वे समस्याओं की जड़ तक जाने में सफल हुए और उनका समुचित समाधान भी निकाल पाए। लोकतंत्र में संविधान सर्वोच्च है एवं उसमें सामान्य जन की सत्ता को सबसे ऊपर माना गया है। अधिकारियों को जनसेवक का दर्जा दिया गया है और उसी प्रकार उनसे व्यवहार की अपेक्षा रहती है। वास्तविकता में बहुत कम अधिकारी ऐसे होते हैं जो जनता के हित में पूरी संवेदनशीलता, ईमानदारी एवं निष्ठा पूर्वक कार्य करते हैं। जो ऐसा करते हैं, उन्हें सामान्य जन का पूरा सम्मान भी मिलता है। कई बार हमने यह देखा है कि कलेक्टर या किसी अधिकारी के स्थानांतरण पर जनता ने हड़ताल तक की है । इस प्रकार के अधिकारियों के स्थानांतरण से स्वार्थ में लिप्त नेताओं ने भले ही राहत महसूस की हो, जनता ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है । किसी भी अधिकारी के लिए इससे बड़ा संतोष क्या हो सकता है कि वह साधारण जन की अधिक से अधिक दुआएं बटोरे। यह सही है कि प्रशासनिक सेवाओं में आने वाले अधिकांश व्यक्ति उच्च शिक्षित और प्रतिभाशाली होते हैं, तब ही वे कड़ी परीक्षा में सफल होते हैं। वे चाहते तो, विकल्प के रूप में किसी निजी कॉर्पोरेट सेवा में जा सकते थे या अपना व्यवसाय करने का रास्ता भी अपना सकते थे। ऐसा करके वे बहुत धन कमा सकते थे। परेशानी तब होती है जब राजकीय सेवा में आने के बाद अधिकारी इस बात का रोना रोते रहते हैं कि उनके साथ वाले अधिकारी जो लोग निजी क्षेत्र में चले गए या विदेश चले गए उन्हें बहुत अधिक वेतन और सुविधायें मिलती हैं। यही सोचकर वे बेईमानी का रास्ता अपना लेते हैं। वे स्वयं की बेईमानी को इस आधार पर उचित सिद्ध करने में लग जाते हैं कि उन्हें भी निजी क्षेत्र या विदेशी कंपनियों में काम करने वाले लोगों जैसी सुविधाएँ प्राप्त करने का अधिकार है। यह सब केवल अपनी बेईमानी को गलत तरह से ढकने का थोथा प्रयास मात्र है। भ्रष्टाचार का कोई औचित्य कभी भी नहीं हो सकता है। जिन व्यक्तियों ने उच्च प्रशासनिक या पुलिस सेवा में आने का निश्चय किया उन्हें यह समझना चाहिए कि उनका लक्ष्य केवल सेवा में आना नहीं होता ,बल्कि सेवा में आने के बाद पद को केवल एक माध्यम के रूप में मानकर जनता की परेशानियां कम करके दुआएं बटोरने का होना चाहिये। नौकरी में आने के बाद क्या वे उल्टे- सीधे तरीके अपना कर जनता को परेशान करके अपने एजेंटों के माध्यम से धन कमाना चाहते हैं अथवा सरकार द्वारा जनता से कर के रूप में एकत्र किए गए धन का अधिकतम लाभ वापस जनता तक किसी न किसी योजना के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं? अच्छा अधिकारी वही माना जाएगा जो सही काम बिना किसी सिफारिश , दबाव या रिश्वत के ,तत्काल कर दे । ऐसा करते समय , वह सामान्य नागरिक के साथ अच्छा व्यवहार करे और उसे उपयुक्त सम्मान भी दे। यदि किसी का काम नियमों के विरुद्ध है तो उसे तत्काल बता दें कि काम होना सम्भव नहीं है। लेखक का अनुभव यह है कि यदि किसी का काम न भी हो पाए , तो नियमों के अनुसार उसे अच्छी तरह आदर पूर्वक कारण सहित समझा दिया जाए तो उसे सामान्यतया कोई शिकायत नहीं होती। परेशानी तब ज्यादा होती है जब किसी व्यक्ति का कोई काम नहीं हुआ किंतु ठीक वैसा ही काम, किसी अन्य व्यक्ति का, उपरी दबाव, सिफारिश अथवा रिश्वत के कारण तत्काल हो जाए। यह स्थिति किसी भी रूप में सुशासन का संकेत नहीं हो सकती। मुख्य सचिव की है सलाह है कि अधिकारियों में दुआएँ बटोरने की इच्छा और क्षमता विकसित होनी चाहिए । अधिकारियों को कानूनों, नियमों की जानकारी तो होनी ही चाहिए किन्तु उससे कहीं अधिक आवश्यकता संवेदनशीलता की है। गत कुछ समय से सरकारी अधिकारियों के वेतनमान पहले की तुलना में अच्छे हो गए हैं और उनका वेतन उनके परिवारों की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है। सामान्यत: उन्हें राजकीय आवास और कुछ मूलभूत सुविधाएं स्वत: ही अपने पद के कारण सरकार से प्राप्त हो जाती हैं। समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, वह अलग से है। यदि अधिकारी गण केवल पैसा कमाने का माध्यम, अपने पद को मान लें तो ऊपर से भले ही जनता उनका सम्मान कर ले किंतु जैसे ही उनका स्थानांतरण होता है , उनके दुर्व्यवहार और भ्रष्टाचार बेईमानी की चर्चा आम हो जाती है। किसी भी अधिकारी की पहचान केवल इसी तथ्य से की जा सकती है कि उसके स्थानांतरण के पश्चात कितने लोग उससे संपर्क रखना चाहते हैं एवं उनसे मिलने की इच्छा रखते हैं। लोगों का काम त्वरित गति से निस्तारित करने में यदि कोई नियम , कानून या प्रक्रिया आड़े आ रही है तो उसे सही करने का काम भी नौकरशाहों का ही है। अस्पष्ट और जटिल नियम, प्रक्रिया या अव्यवहारिक नियम केवल भ्रष्टाचार को ही बढ़ाने का काम करते हैं। अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में रात्रि विश्राम करने की जो परंपरा थी , उसे पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है । जब कोई अधिकारी किसी क्षेत्र में रात्रि विश्राम करता है तो उससे विभिन्न वर्गों के लोग आकर मिलते हैं और तब उसे वास्तविक स्थिति जानने में सहायता मिलती है । यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि रात्रि विश्राम करने का कोई विकल्प नहीं है। यह अवश्य ध्यान रखना होगा कि उच्च अधिकारियों के रात्रि विश्राम का भार स्थानीय अधिकारियों / कर्मचारियों पर ना पड़े एवं सादगी उनके व्यवहार में रहे । कई बार सर्किट हाउस का भुगतान तक अधिनस्थों को करना पड़ता है। उच्चाधिकारियों के दौरे पर होने वाले खर्चे की आड़ में स्थानीय अधिकारियों को एक प्रकार से बेईमान होने का लाइसेंस मिल जाता है। सादगी पूर्ण व्यवहार करने वालों को आजकल मूर्ख माना जाता है। कई बार परिजनो के दबाव में अधिकारी गण, विशेष रूप से उच्च सेवाओं के अधिकारीगण, अपने स्टेटस को बनाए रखने के दबाव में न केवल बेईमान हो जाते हैं बल्कि सादगी को अपनी कमजोरी मानने लगते हैं। यह मानना होगा कि सादगी, एक प्रकार का गुण है न कि अवगुण । उच्च सेवा का अधिकारी जितना सादगी पूर्ण व्यवहार करेगा उतना ही वह जनता का विश्वास अर्जित कर पाएगा और उनकी समस्याओं को दूर करने में भी उतने ही संतोष का अनुभव प्राप्त करेगा। यह वही अनुभव कर सकते हैं जिन्होंने ऐसा किया हो। कई लोग कभी धन्यवाद के दो शब्द भले ही न कह पाएँ, किंतु मन से तो वह सदैव आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं देते ही हैं। और इसी प्रकार का आशीर्वाद और शुभकामनाएं किसी भी अधिकारी के लिए सबसे बड़ी पूंजी हो सकती है। ऐसे ही लोग सेवानिवृत होने के बाद भी बड़े संतोष के साथ जीवन जी सकते हैं। अब तो यह देखना यह है कि मुख्य सचिव की सलाह को किस प्रकार से आत्मसात करते हुए अधिकारी गण अपने व्यवहार और कार्य में इसे प्रदर्शित करते हैं और जनता के कार्य में तत्परता दिखाते हैं । यदि ऐसा हो पाया, तो जिस विश्वास के साथ मुख्यमंत्री, वरिष्ठता को लांघ कर नए मुख्य सचिव को लाए हैं, वह सही सिद्ध होगी। मुख्य सचिव के पास तीन वर्ष से अधिक का समय है जो अपनी सोच को अधिकारियों के माध्यम से वास्तविकता में परिणत करने के लिए पर्याप्त है। नए मुख्य सचिव को इस पुनीत उद्देश्य में सफल होने के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं!

किसी भी अधिकारी के लिए इससे बड़ा संतोष क्या हो सकता है कि वह साधारण जन की अधिक से अधिक दुआएं बटोरे। यह सही है कि प्रशासनिक सेवाओं में आने वाले अधिकांश व्यक्ति उच्च शिक्षित और प्रतिभाशाली होते हैं, तब ही वे कड़ी परीक्षा में सफल होते हैं। वे चाहते तो, विकल्प के रूप में किसी निजी कॉर्पोरेट सेवा में जा सकते थे या अपना व्यवसाय करने का रास्ता भी अपना सकते थे।

अतिथि सम्पादक
राजेन्द्र भाणावत, आई.ए.एस. (रिटायर्ड)

नई सरकार की प्राथमिकताएं : राजकीय वाहनों पर व्यय में मितव्यता

भागीरथ शर्मा

हमारे शासनतन्त्र में चालक सहित राजकीय वाहन की प्रणाली ब्रिटिश शासन एवं रजवाडों की देन हैं। उस समय की सुरक्षात्मकता की दृष्टि से यह आवश्यक भी थी परन्तु हमने इस प्रणाली को अपनाकर राजकोष पर भारी वित्तीय भार पैदा कर लिया है। वस्तुत: अब तो यह ''आवश्यकता के बजाय स्टेटस व शान का प्रतिक'' बन गया है। हर छोटा बड़ा अधिकारी यह महसूस करने लगा है कि लाल पट्टी की गाडी के बिना उसे कोई अधिकारी के रूप मे पहचानेगा ही नहीं। इस प्रवृति के दुष्परिणाम स्वरूप वर्ष दर वर्ष वाहनों की संख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई हैं।

सरकारी वाहनों में कारों व जीपों की यह संख्या वर्ष 1980-81 में 7489 थी जो वर्ष 98-99 तक बढकर 15269 हो गई जबकि ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन आदि समृद्ध राष्ट्रों में चालक सहित राजकीय वाहन उनकी वित्तीय क्षमता से बाहर माने जाते हैं एवं इसे विलासिता की निशानी कही जाती है। इन देशों में तो केन्द्र सरकार के सभी सचिवों एवं मंत्रीयों तक के पास भी राजकीय वाहन नहीं है वे अपने वाहनों से कार्यलय आते जाते है एवं बाहर दौरों में भी अधिकांशत: अपने ही वाहन काम में लेकर माईलेज भत्ता ले लेते है।

आयोग ने अपने प्रतिवेदन में यह चौकाने वाला तत्थ उजागर किया है कि स्टेट मोटर गैरेज का औसत वाहन परिचालन व्यय 18.09 रू. प्रति किलोमीटर आता है। इस दर से आकलन करे तो सभी 15269 वाहनों पर औसतन 18000 किलोमीटर प्रतिवर्ष चलने पर लगभग 500 करोड़ रूपये का वार्षिक व्यय होता है। आयोग ने स्टेट मोटर गैरेज के अधिक व्यय के कारकों को दृष्टिगत रखते हुए पूरे राज्य के लिए भी वर्ष 1999-2000 के पैट्रोल मूल्यों के आधार पर 15.84 रूपये प्रति किलोमीटर हर राजकीय वाहन का औसत परिचालन व्यय आकलित किया हैं। इस दर से भी तत्समय 435 करोड रूपये का वार्षिक व्यय भार आता था जबकि पेट्रोल की कीमतों में अब तक हुई लगभग सवा गुणा वृद्वि को दृष्टिगत रखते हुए यह व्यय भार अब 500 करोड को भी पार कर चुका है।

आयोग के आकलन के अनुसार यदि पुर्वानुसार ही दौरों का माईलेज यथावत रखते हुए एवं कतिपय उच्चाधिकारीगण को 30 से 100 लीटर का प्रतिमाह पेट्रोल भत्ता स्थानीय यात्राओं के लिए देने के उपरान्त भी यदि बाहर दौरों के लिए राजकीय वाहन के स्थान पर टैक्सी का विकल्प अपनाया जाये, जो 3.50 से 4 रूपये प्रति किलोमीटर उपलब्ध हो जाती है, तो यह कुल व्यय केवल 100 करोड रूपये प्रतिवर्ष ही रह जायेगा एवं इस प्रकार 335 से 400 करोड रूपये प्रतिवर्ष की बचत हो सकेगी।

गत वर्षो में राज्यकोष पर भारी व्यय को देखते हुए राजकीय वाहन कम करने हेतु कई बार कोशिशें की गई पर इस निर्णय में बाधक तत्व इतने शक्तिशाली है कि उच्च स्तर पर स्पष्ट मंशा होते हुए यह निर्णय येन केन प्रकारेण टलता ही आ रहा है। गत सरकार द्वारा कुछ समय पूर्व 'इयर मार्क' गाड़ियां वासस लेकर इस दिशा में सुधार की कोशिश अवश्य की गई है लेकिन इस प्रयास को भी लगभग सभी गाड़ियां नीलाम नही करने के निर्णय व अधिकारियों को अपने व्यय पर परिचालन हेतु गाड़ियां देकर निष्प्रभावित कर दिया है। पैट्रोल व्यय तो पूरे व्यय का एक अंशमात्र है। बिना परिचालित खडी गाडी पर भी चालक के वेतन, रख-रखाव आदि का व्यय ही लगभग 20000 रू. प्रतिमाह आता है। अत: इस मद से कोई उल्लेखनीय बचत नही हो सकी है।

आयोग द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुसार प्रोटोकोल, मंत्रीगण, कतिपय शीर्ष उनचाधिकारीगण, कानून व्यवस्था, जिला एवं पुलिस प्रशासन, आपातकालीन सेवाओं आदि के लिए 3269 वाहन छोडकर 12000 वाहन वापस लेने एवं उनकी एवज में बाह्य यात्रा हेतु निजी वाहन से यात्रा करने पर 3.75 रू. प्रति किलामीटर की दर से यात्रा भत्ता या टैक्सी पूल से वाहन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया था। जिन अधिकारीगण को स्थानीय यात्राओं के लिए 'इयर मार्क' राजकीय वाहन उपलब्ध था उन्हें स्थानीय यात्राओं हेतु पद व स्थान के अनुसार 100 लीटर से 30 लीटर तक पैट्रोल की कीमत हर माह वेतन में जोडने का प्रस्ताव दिया गया था। आयोग द्वारा प्रस्तावित योजना के लागू करने पर एवं 3269 राजकीय वाहनों को कानून व्यवस्था आदि के लिए रखने के बावजुद भी सभी व्यय घटकर राज्य कोष में 270 करोड रूपये की बचत का अनुमान लगाया गया है। वाहनों को पुस्तकीय कीमत पर भी निस्तारण करने पर लगभग 60 करोड रूपये की आय होगी जिसका उपयोग अधिकारीगण को निजी वाहन क्रय करने हेतु ऋण के रूप में किया जा सकता है। इससे राजकीय वाहनों के भारी दुरूपयोग पर भी सीधा अंकुश लग जायेगा।

निस्तारित किये जाने वाले वाहनों को ''पुस्तकीय कीमत'' पर अधिकारीगण या स्वेच्छा से सेवानिवृति चाहने वाले वाहन चालकों को मय टैक्सी लाईसेंस के दिये जा सकेगें। ऐसे वाहन चालक अपने वाहनों का जिला स्तर पर प्रस्तावित ''टैक्सी पूल'' में पंजीयन करवाकर राज कार्य में टैक्सी को चला सकेगें। प्रस्तावित योजना के अनुरूप ही कई ऐसे राज्य यथा हिमाचल प्रदेश, आसाम, गुजरात आदि में भी विभिन्न योजनाएं लागू है। राजस्थान में इस योजना का नई सरकार द्वारा प्राथमिकता से तत्काल लागू किया जाना तो वर्तमान वित्तीय संकट को मध्य दृष्टि रखते हुए नितान्त आवश्यक है।

भागीरथ शर्मा,
आई.ए.एस, (से.नि.)

विश्वविद्यालय वह स्थान है, जहां से युवा पीढ़ी भविष्य में कुछ बनने के सपने संजोती है : मिश्र

राज्यपाल मिश्र ने राजस्थान विवि. के 78 वें स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की

जयपुर। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विकसित भारत-2047 के लिए विश्वविद्यालयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केन्द्र के रूप में अपनी पहचान बनाने के साथ ही वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप अपने आपको तैयार करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय शैक्षिक गुणवत्ता, शोध-अनुसंधान की मौलिक दृष्टि के साथ अपने आपको इस तरह से विकसित करें कि विदेशों से अभिभावक अपने बच्चों को भारत पढ़ने के लिए भेजने हेतु उत्सुक रहें। उन्होंने विकसित भारत के संकल्प के लिए उच्च शिक्षा से जुड़े युवाओं को आगे आकर महती भूमिका निभाने का भी आव्हान किया है। राज्यपाल कलराज मिश्र मिश्र सोमवार को राजस्थान विश्वविद्यालय के 78 वें स्थापना दिवस पर संबोधित कर रहे थे।

राजस्थान विश्वविद्यालय के 78 वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, कुलपति प्रो. अल्पना कटेजा आदि मौजूद रहे।

- **उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने विश्वविद्यालयी शिक्षा के जरिए युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए सक्षम बनाने पर जोर दिया।**

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय वह स्थान है, जहां से ज्ञान के बीज अंकुरित होते हैं। यहीं से हमारी युवा पीढ़ी भविष्य में कुछ बनने के स्वपन्न संजोती है। उन्होंने कहा कि आजादी के सौ वर्ष पूर्ण होने के अमृतकाल में न केवल हमें विकास के लिए निरंतर कार्य करना है बल्कि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिणक तथा लैंगिक असमानताओं को दूर कर तेजी से आगे बढ़ने की भी जरूरत है। देश के विश्वविद्यालयों को इसका संवाहक बनना चाहिए। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों को अपने यहां ऐसे पाठ्यक्रम निर्मित करने पर जोर दिया जो युवाओं को कौशल संपन्न करने के साथ ही उनकी भविष्य की दृष्टि को विकसित कर सके। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए समग्रा शिक्षा, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी के एकीकरण पर भी विशेष कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय युवाओं को यह विश्वास दिलाए कि उनके निर्णयों पर समाज भरोसा करता है। उन्होंने विश्वविद्यालयों द्वारा युवाओं को मानवीय आदर्शों और राष्ट्र निर्माण से जुड़े कार्यों और प्राथमिकताओं से परिचित कराने के लिए भी कार्य करने का आव्हान किया। मिश्र ने राजस्थान विश्वविद्यालय के गौरवमय इतिहास की चर्चा करते हुए विश्वविद्यालय को भविष्य का ऐसा रोडमैप बनाने के लिए भी कहा जिससे यहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शोध की मौलिक दृष्टि के साथ युवा उद्यिमता विकास के लिए प्रभावी कार्य हो सके। उन्होंने कहा कि शिक्षा अनुभवों के निरंतर पुनर्निर्माण से जीवन जीने की प्रक्रिया है। यह विद्यार्थियों में निहित उन तमाम क्षमताओं का विकास करती है जो उसे भविष्य की चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए सक्षम बनाती है। उन्होंने नई शिक्षा नीति के आलोक में शिक्षा का व्यावहारिक बनाने, खेल और सांस्कृतिक प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करने और विश्वविद्यालय के आदर्श वाक्य ''धर्मो विश्वस्य जगत: प्रतिष्ठा'' के संदर्भ में समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहते हुए विकसित भारत 2047' में सभी को मिलकर योगदान देने का आव्हान किया।

इससे पहले राज्यपाल मिश्र ने विश्वविद्यालय में मानविकी पीठ के नवीनीकरण के हुए कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होने कहा कि मानविकी मानव अध्ययन से जुड़ा क्षेत्र है। इसके अंतर्गत भारत के गौरवमय अतीत से प्रेरणा लेते हुए भविष्य की उज्ज्वल दृष्टि पर हमें ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने विश्वविद्यालयी शिक्षा के जरिए युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए सक्षम बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में रिक्त पद भरने के लिए प्रभावी प्रयास होंगे। वहीं सांसद रामचरण बोहरा ने नई शिक्षा नीति के साथ विकसित भारत के लिए चुनौतियों को अवसरों में बदलने की बात कही। विधायक और पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ ने विश्वविद्यालय से अपने जुड़ाव की स्मृतियां साझा करते हुए शिक्षा क्षेत्र में राजस्थान को अग्रणी बनाए जाने के लिए मिलकर कार्य करने पर जोर दिया। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. अल्पना कटेजा ने विश्वविद्यालय के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों और स्थापना दिवस पर भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार से अवगत कराया। राज्यपाल मिश्र ने आरम्भ में सभी को संविधान की उद्देशिका का वाचन करवाया और मूल कर्तव्य पढ़कर सुनाए।

रेल विभाग के अधिकारियों ने दौसा से डिडवाना तक रेलवे लाइन का प्री-स्पीड ट्रायल किया

दौसा, (निसं)। दौसा-गंगापुर सिटी रेलवे बहुप्रतीक्षित परियोजना का सोमवार को दौसा से लेकर डिडवाना तक रेलवे अधिकारियों ने रेलवे के विशेष निरीक्षण यान से पटरी का बारीकी से शुरु होने वाले रेल संचालन को लेकर प्री-निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के बाद क्षेत्र की पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बड़ी महत्वाकांक्षी रेल परियोजना के फरवरी माह के अंत तक शुरू होने की उम्मीद बनी है।

इस दौरान दौसा से डिडवाना रेलवे सुरंग तक प्रत्येक स्टेशन व ब्रिज और पटरियों का रेलवे सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा बारीकी से निरीक्षण किया गया। इस दौरान रालावास गांव के ग्रामीणों ने रेलवे लाइन से होने वाले रास्ते अवरुद्ध की शिकायत रेलवे सेफ्टी ऑफिसर से की तो उन्होंने तुरंत अधिशासी अभियंता को निर्देश देते हुए कहा कि इस प्रकरण को देखकर उचित समाधान करें। रेलवे सुरक्षा अधिकारी आरएस रनोट ने बताया कि मुख्य सुरक्षा आयुक्त के द्वारा जल्द ही दौसा से डिडवाना तक रेलवे लाइन का स्पीड ट्रायल किया जाएगा। ऐसे में दौसा से डिडवाना तक रेलवे लाइन का निरीक्षण किया जा रहा है, हालांकि दौसा से डिडवाना तक रेलवे लाइन का पूर्व में भी स्पीड ट्रायल हो चुका है, लेकिन इस रेल नही चली थी। ऐसे में काफी समय होने के बाद वापस इसका स्पीड ट्रायल होगा।बारीकी से हर बिंदु का निरीक्षण किया गया है। उन्होंने बताया कि लालसोट से गंगापुर सिटी रेलवे लाइन का स्पीड ट्रायल हो चुका है और उसकी अप्रूवल भी मिल चुकी है जैसे ही दौसा से डिडवाना तक स्पीड ट्रायल होगा और इसकी अप्रूवल मिलेगी, तो जल्द ही दौसा से गंगापुर सिटी रेलवे तक रेल सेवाएं शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यह लोगों के लिए बहुत खुशी की बात होगी लगभग फरवरी में दौसा से गंगापुर सिटी तक रेल सेवाएं शुरू हो जाएगी। वहीं रेलवे टनल का काम भी तेजी से चल रहा है जिसे भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। यह दौसा-गंगापुर सिटी रेल परियोजना तत्कालीन केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश पायलट का सपना था जो अब तक की रही सरकारों की उदासीनता के चलते बजट के अभाव में रेग रेग कर चल रही थी। गौरतलब है कि लोगों में इस दौसा गंगापुर सिटी रेल परियोजना का क्रेज इस कदर था कि 2003 में दोसा गंगापुर रेल परियोजना के बूते भाजपा लालसोट से बड़े लंबे समय बाद भाजपा का विधायक चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी।

दौसा-गंगापुर सिटी रेल लाइन का रेलवे अधिकारियों द्वारा प्री स्पीड ट्रायल किया गया।

- **दौसा-गंगापुर सिटी रेल परियोजना तत्कालीन केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश पायलट का सपना था**

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

मंगलवार 9 जनवरी 2024

पौष मास कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी तिथि, विक्रम सम्वत 2080, ज्येष्ठा नक्षत्र रात्रि 9.14 तक, वृद्धियोग रात्रि 12.27 तक, गरकरण दिन 11.12 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 9.11 से धनु राशि में संचार करेगा। ग्रह स्थिति - सूर्य-धनु, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-धनु, बुध-धनु, गुरु-मेष, शुक्र-वृश्चिक, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में संचार करेगा। आज मौस प्रदोष व्रत, श्री चन्द्रमा जयंती, मास शिवरात्रि है। भद्रा रात्रि 10.25 से आरम्भ होगी।

श्रेष्ठ चौघडिया - अमृत सूर्योदय से 8.39 तक शुभ - 9.57 से 11.59 तक, चर 9.58 से 11.16 तक, लाभ-अमृत 11.16 से 1.52 तक। राहुकाल - 3.00 से 4.30 तक, सूर्योदय 7.22 सूर्यास्त 5.47

मेष
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं।

वृष
परिवार में आपसी सहयोग समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। आज सामुहिक प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

मिथुन
विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी।

कर्क
व्यावसायिक विवादों से राहत मिल सकती है। अटके हुए व्यावसायिक कार्य बनने लगेंगे। नौकरी पैशा व्यक्तियों को भाग-दौड से राहत मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। परिवार में अथितियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है। परिवार में वाद-विवाद टालना ठीक रहेगा।

कन्या
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। घर-परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह संपन्न हो सकते हैं।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नौकरी पैशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है।

धनु
स्वभाव की तेजी पर नियंत्रण रखें। महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में जल्दबाजी करना ठीक नहीं रहेगा। अनावश्यक धन खर्च होगा। मन में असंतोष बना रहेगा।

मकर
आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। संभावित स्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

मीन
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता से बनने लगेंगे। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा।